

# शिक्षित और समृद्ध प्रदेश के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : भजनलाल शर्मा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश की उन्नति में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है तथा राज्य सरकार आपगो अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप युवा शक्ति के उन्नयन के साथ शिक्षित और समृद्ध प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात के दौरान सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी का मानना है कि इस देश में युवा, महिला, किसान, गरीब जैसे चार वर्ग हैं, जिनके उत्थान के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत एवं संविधान बचाने का ढोंग कर रहे हैं, उनके द्वारा इस दिन देश में लागू किया गया आपातकाल लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान है।

शर्मा मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में संविधान संरक्षण मंच द्वारा आयोजित 'संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता' विषयक संगोष्ठी में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार संविधान को सर्वोपरि मानती है। उन्होंने देश के संविधान की रक्षा का अपना वचन बार-बार दोहराया है और प्रदेश में भी संविधान की रक्षा का दायित्व हम पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प समय में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि एक हजार से बढ़ाकर 1150 रुपए करने, किसान सम्मान निधि की राशि बड़ा कर 8 हजार रुपए करने, 73 लाख परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से आह्वान किया कि वंचित तबके को केन्द्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराए ताकि वे भी समाज की



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अपने निवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात की।

के साथ बेटों को भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी परिवर्तित बजट में युवाओं के कल्याण तथा सशक्तीकरण के लिए

विभिन्न निर्णयों का समावेश किया जाएगा। इस अवसर पर युवाओं ने विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने, रोजगार के लिए विशेष अभियान, खेल

सुविधाओं का विस्तार, महिला सुरक्षा, परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने, भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव भी दिए। उन्होंने

- 'देश और प्रदेश की उन्नति में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण'
- 'बेटियों के साथ बेटों को भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान करेगी राज्य सरकार'

कहा कि छात्र संगठनों को युवाओं की समस्याओं को उजागर करने के साथ-साथ उनके समाधान का भी माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के साथ युवा सशक्तीकरण व छात्र कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इसके पहले संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर ध्येय यात्रा पुस्तक भेंट की। इस दौरान राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मौजूद थे।

## सीकर रोड पर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को 36.88 करोड़ लागत से बन रहे सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट शिलान्यास किया। दिया कुमारी ने कहा कि मानसून में जल-भराव की समस्या से सभी लोग बरसों से परेशान थे, परन्तु आज इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट अब इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल पायेगा।

उन्होंने कहा कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट, रेलवे ओवर ब्रिज, बालिका कॉलेज और सेंट्रल हास्पिटल आ रहे हैं। अन्य जनसमस्याओं की निराकरण के लिए मैं जल्द ही इलाक़े में साप्ताहिक जनसुनवाई शुरू करने जा रही हूँ। सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा होने से भवानी निकेतन, देहर के बालाजी, अल्का सिनेमा, 1 नंबर सन एडव मून, मुसलीपुरा एवं विद्याधर नगर आदि क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को आलाभान में सुविधा मिलेगी। वार्ड नं 4 में दो करोड़ 30 लाख रुपये के खिलाफ राशियाँ कॉलोनी से लालाराम नगर बढारना में जल निकास ड्रेनेज का निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी, समस्त मंडल अध्यक्ष, समस्त वार्ड पार्षद, मोर्चा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल पदाधिकारी, कार्यकर्ता व विद्याधर नगर के सम्मानित जन मौजूद रहे।

## एक नेता की निजी अदावत का नुकसान उठाया जयपुर कांग्रेस ने

जयपुर, (का.प्र.)। एक कांग्रेस नेता की निजी अदावत जयपुर शहर की पूरी कांग्रेस को पिछले 2 साल से भारी पड़ रही है और इसका नुकसान न सिर्फ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ा और आगे आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को यह नुकसान होना चुन है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर को लेकर एक तरह से निजी लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। दूसरी ओर पूरी कांग्रेस 2 साल से इस लड़ाई को तमाशबीन बनकर देख रही है।

यह पूरी कहानी तब से है, जब जयपुर में दो नगर निगम बनाए गए थे। सभी को यह बात याद होगी कि पहले सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर का हिस्सा बनाया गया था और मालवीय नगर हेरिटेज नगर निगम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उसे समय के बिनेट मंत्री पद पर रहते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस सीमांकन को बदलवाकर सिविल लाइन को हेरिटेज का हिस्सा बनवाया, तो मालवीय नगर ग्रेटर का हिस्सा बन गया। इसका फायदा यह हुआ कि मुस्लिम वोटर्स के सहारे कांग्रेस का बोट बना, लेकिन मुस्लिम पार्षद 80 प्रतिशत जीतने के बावजूद

- दो साल से कांग्रेस बनी रही मूकदर्शक, इसका नुकसान कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ा
- चर्चा है कि यह लड़ाई कांग्रेस पार्षदों की नहीं, बल्कि खाचरियावास और मुनेश गुर्जर की है

खुद की ओबीसी महिला को इसलिए महापौर नहीं बनाया जाए, क्योंकि जयपुर के दोनों मुस्लिम विधायक रफीक खान और अमीन कागजी नहीं चाहते थे, कि कोई और मुस्लिम नेता जयपुर में उभरे। इसका फायदा यह हुआ कि प्रताप सिंह अपनी खाचरियावास ने सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से जीती मुनेश गुर्जर को महापौर बनाया दिया, लेकिन ऐसे में उप महापौर का पद मुस्लिम के हिस्से गया और प्रताप सिंह खाचरियावास के बेहद नजदीकी पार्षद मनोज मुद्गल उप महापौर बनने से चूक गए।

चर्चा है कि कांग्रेस 2 साल से लगातार इस तमाशे को देख रही है, कि किस तरह से महापौर मुनेश गुर्जर से प्रताप सिंह खाचरियावास के राजनीतिक संबंध बिगड़ने के बाद उन्होंने हर दिन महापौर को हटाने का हर प्रयास किया। जब ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद जब एसीबी ने महापौर

के घर छापा मारा और उनके पति की गिरफ्तारी हुई, तो खाचरियावास और उनके साथ ही अमीन कागजी और रफीक खान गुट के पार्षदों की तरफ से इस तरह का दबाव बनाया जाता रहा। हालांकि महापौर दो बार हाईकोर्ट से स्टे लेकर पद पर बैठ गए।

अब एसीबी को महापौर की मिलीभगत के सबूत मिले हैं, लेकिन अभियोजन स्वीकृति सरकार जब तक नहीं देती, तब तक महापौर पद पर बैठी है। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के नेता पहले भी मूकदर्शक थे आज भी सिर्फ नोटिस दिए गए हैं। हालांकि जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर आर तिवारी ने इस मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और जयपुर के प्रभारी विधायक रोहित बोहरा को स्पष्ट कहा है कि अगर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई, तो पार्टी में अनुशासनहीनता के मामले और बढ़ेंगे।

## विधायक आवास परिसर में सुविधाओं का विस्तार

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाानी ने मंगलवार को यहां विधायक आवास परिसर में बैंक एटीएम ई-कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ, सरस डेयरी और चिकित्सालय का उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्रीजोगाराम पटेल, डेयरी मंत्रीजोगाराम कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री गोतम कुमार, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम, विधानसभा के सरकारी मुख सचेतक जोगेश्वर गर्ग की मौजूदगी में किया।

देवनाानी ने कहा कि विधायक आवास परिसर में लगभग 125 विधायक और उनके परिवारजन निवास कर रहे हैं। परिसर में यहां के निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। एसबीआई बैंक एटीएम का ई-कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ का विविध वस्तु भण्डार, सरस डेयरी का पालर और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के लिये शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का शुभारम्भ किया गया है। भविष्य की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाओं का भी समयानुसार विस्तार किया जायेगा।

देवनाानी ने कहा कि चिकित्सालय में वर्तमान में एलेोपैथी और होम्योपैथी चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। भविष्य में जरूरत के अनुरूप आयुर्वेद चिकित्सकों की भी यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। चिकित्सालय का समय भी आवश्यकतानुसार बढ़ाया जायेगा। परिसर में एक समिति का गठन किया गया है, जो यहां निवास कर रहे लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि परिसर की सुरक्षा के भी पृष्ठता प्रबंध किये गये हैं। यहां रहने वाले विधायक, उनके परिवारजन और उनके अतिथि की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं।

देवनाानी ने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सभी को साथ लेकर चलने के बेहतर प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के आरम्भ होने से पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात की जायेगी। आगामी 2 जुलाई को प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक का मकसद है कि सदन नियमों के अनुसार शांतिपूर्ण चले।

## तबादले पर अधिकरण ने रोक लगाई

जयपुर, (का.सं.)। सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पंचायती राज विभाग के अधिकरण को तबादला आदेश उसके कार्यग्रहण करने के तीन दिन बाद रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव, सवाई माधोपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और गंगारपुर सिटी जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकरण ने पूछा है कि जब तबादला आदेश की पालना में कार्य ग्रहण कर लिया गया तो ट्रांसफर आदेश को रद्द क्यों किया गया। अधिकरण ने यह आदेश देना कि विधानसभा की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था। गत सात सत्रों को उसका तबादला यहां से गंगारपुर सिटी जिला परिषद में कर दिया।

## साइबर थाने की खिड़की से कूद कर अपराधी भागा

जयपुर। साइबर थाने से सोमवार देर रात एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। जानकारी के अनुसार साइबर ठगो के आरोप में साइबर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। कमरे में पृष्ठताछ के दौरान पुलिसकर्मी के बाहर आने पर अपराधी खिड़की से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश में जगह-जगह दृष्टि दी। लेकिन उसका कोई पता नहीं लग सका। इस संबंध में पुलिस ने विधायकपुरी थाने में फरार बदमाश के खिलाफ पुलिस कस्टडी से भागने का मामला दर्ज करवाया है।

साइबर थानाधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि पुलिस कस्टडी से भागने वाला आरोपी दीपक सिंह (21) पुत्र राजेन्द्र सिंह खण्डार सवाई माधोपुर का रहने वाला है। साइबर थाने में दर्ज मामले में आरोपी दीपक सिंह के साइबर फ्रॉड के लिए फेक अकाउंट उपलब्ध करवाने का पता चला था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दृष्टि साइबर आरोपी दीपक सिंह को रविवार शाम गिरफ्तार किया था। पुलिस टीम ने सोमवार दोपहर आरोपी को कोर्ट में पेश कर दो दिन का रिमांड लिया था।

## दो स्थानों से सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को हटाया



जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने जून-9 में गोमती नगर द्वितीय सांगानेर में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बनाई जा रही अवैध दुकान को ध्वस्त किया।

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जून-7 में ग्राम सिरसी में रोड़ पर सड़क सीमा में आ रहे कब्जा-अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। जून-9 में गोमती नगर द्वितीय सांगानेर में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बनाई जा रही अवैध दुकान को प्रारम्भिक स्तर पर पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही जून-14 में ग्राम बिलवा चन्द्रवन के सामने रोड़ सीमा को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेश कुमार शर्मा जून-7 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सिरसी रोड़ पर कब्जा-अतिक्रमण कर कन्टेनर डीपो लगाकर, पत्थर मशीन इत्यादि डालकर किये गये कब्जे-अतिक्रमण को आज जून-7 में रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी

जून-7 स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाते, लेबर गार्ड एवं जून में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा जून-8 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गोमती नगर द्वितीय सांगानेर में अवैध रूप से बेसमेन्ट खोदकर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बनाई जा रही अवैध दुकान को आज जून-8 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रारम्भिक स्तर पर ही ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जून-8 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाते, लेबर गार्ड एवं जून में

पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

इसी प्रकार जून-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बिलवा चन्द्रवन के सामने रोड़ सीमा पर कब्जा-अतिक्रमण कर थड़ी, छप्पर पोष इत्यादि लगाकर किये गये कब्जे-अतिक्रमण को आज जून-14 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जून-14, 10 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाते, लेबर गार्ड एवं जून में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

## डी-मार्ट से 1.80 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार झोटवाड़ा जून की टीम द्वारा सिरसी रोड़ वार्ड नं. 48 स्थित निर्माणधीन डी-मार्ट से 1.80 लाख रुपए के राजस्व का जुर्माना राशि वसूल किया। उपायुक्त झोटवाड़ा जून कमलेश मीना ने बताया कि सिरसी रोड़ वार्ड नं. 48 स्थित डी-मार्ट के निर्माणधीन भवन की निर्माण सामग्री सरकारी भूमि पर डालकर अस्थायी अतिक्रमण किये जाने पर नोटिस जारी किये गये। नोटिस दिये जाने के बाद झोटवाड़ा जून की संयुक्त टीम ने डी-मार्ट की निर्माणधीन बिल्डिंग के ठेकेदार और प्रतिनिधि से 1 लाख 80 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल की।

## ग्रेटर निगम 1000 रु. में खरीदेगा ट्री गार्ड, हैरिटेज निगम में 2100 रु. चुकाने की तैयारी!

इस मानसून हैरिटेज निगम 2.66 करोड़ में खरीदेगा 12700 ट्री गार्ड, जबकि ग्रेटर में 74 लाख की लागत से लिए जाएंगे 7400 ट्री गार्ड

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। हैरिटेज नगर निगम की उद्यान शाखा इन दिनों चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बेवजह करोड़ों रुपए उड़ा रही है। हैरिटेज निगम ने इस मानसून में लगाए जाने वाले पौधों की सुरक्षा के लिए 12700 ट्री गार्ड का टेंडर करीब 2.66 करोड़ रुपए में निकाला है, यानी कि 1 ट्री गार्ड करीब 2100 रुपए में खरीदा जाएगा।

ताजुब की बात यह है कि ग्रेटर निगम में भी 7400 ट्री गार्ड लिए जाने हैं, लेकिन इनकी अनुमानित लागत सिर्फ 74 लाख रुपए रखी गई है, यानी कि एक ट्री गार्ड सिर्फ 1000 रुपए में खरीदा जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जयपुर के दोनों नगर निगम की उद्यान शाखा की कार्यशैली में इतना भारी अंतर क्यों है?

सूत्रों की माने तो हैरिटेज नगर

- सूत्रों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन ने इस बार भी शर्त यह रखी है कि, जो फर्म इन टेंडरों में भाग लेगी, उसे पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में सरकारी विभाग, निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोहे के ट्री गार्ड आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए, जो कि इन टेंडरों की एक तिहाई राशि के बराबर होना चाहिए। जबकि ठेकेदारों का कहना है कि ट्री गार्ड की क्वालिटी देखने के बजाय अधिकारी बेवजह ही शर्त लगाकर चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

निगम की उद्यान शाखा ने पिछले दिनों हवामहल-आमेर और किसानपोल जून के लिए 4000, आदर्श नगर के लिए 4500 और सिविल लाइन्स के लिए 4200 ट्री गार्ड खरीदने के लिए निविदा जारी की है। बताया जा रहा है कि इन कुल 12700 ट्री गार्ड की अनुमानित

लागत करीब 2.66 करोड़ रुपए रखी गई है। हैरिटेज निगम प्रशासन ने ट्री गार्ड की जो साइज और ऊंचाई तय की है, जिसके अनुसार इसका वजन अनुमानित करीब 16-17 किलो होगा। वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नगर निगम ने जो 7500 ट्री गार्ड मांगे हैं, उनका

अनुमानित वजन करीब 9 किलो होगा। खास बात यह है कि ग्रेटर निगम मात्र 1000 रुपए में ट्री गार्ड लेगा, जबकि हैरिटेज निगम करीब 2100 रुपए में। सूत्रों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन ने इस बार भी अलग शर्त यह रखी है कि, जो फर्म इन टेंडरों में भाग लेगी, उसे पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में सरकारी विभाग, निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोहे के ट्री गार्ड आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए, जो कि इन टेंडरों की एक तिहाई राशि के बराबर होना चाहिए। जबकि ठेकेदारों का कहना है कि ट्री गार्ड की क्वालिटी देखने के बजाय अधिकारी बेवजह ही शर्त लगाकर चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

चर्चाएं यह है कि अधिकारियों ने यह शर्त उन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए रखी है जो पहले नगर निगम में

ट्री गार्ड सप्लाय का काम कर चुके हैं। हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रैक्टर्स सोसाइटी समेत करीब आधा दर्जन फर्मों ने इन शर्तों को लेकर निगम प्रशासन के समक्ष आपत्ति भी जताई थी, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सूत्रों की माने तो ग्रेटर और हैरिटेज निगम पिछले कई वर्षों से ट्री गार्ड की खरीद करता आ रहा है। हर साल करीब 15 से 20 हजार ट्री गार्ड लिए जाते हैं, लेकिन अगला मानसून आते आते यह ट्री गार्ड गायब हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि पार्षदों के अनुरंसा पत्र पर पेड़ और ट्री गार्ड लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाने के कारण इन ट्री-गार्ड का कोई अंता-पता नहीं रहता। नियमानुसार उद्यान शाखा के अफसरों को बकायदा रजिस्टर में ट्री गार्ड की एंट्री करनी होती है, लेकिन पिछले कई सालों से यह काम भी बंद है।